संपादकीय

जात ही पूछिए नेता की

आखिरकार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी महत्वाकांक्षाओं के पत्ते खोल ही दिये। हरियाणा में खुद की जड़ें होने की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल हकीकत में अपनी पार्टी की जड़ें नहीं जमा पाये। दिल्ली से बिल्कुल सटे हरियाणा में पार्टी को सत्ता में लाने की पुरजोर कोशिश करने की बजाय केजरीवाल पंजाब से गोवा तक का फेरा लगाते रहे। ?अब आप ने वर्ष 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में दल के मंसूबे जाहिर करते हुए पार्टी अध्यक्ष और केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले नवीन जयहिंद को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का संभावित चेहरा घोषित कर दिया है। निश्चय ही नवीन जयहिंद की हरियाणा में अच्छी-खासी सक्रियता रही है। मगर इस घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अब उनका नाम मीडिया में पंडित नवीन जयहिंद के रूप में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या 'जयहिंद' में उनकी पहचान उजागर नहीं हो पा रही थी? क्या पंडित लिखने से उनका जनाधार बढ़ जायेगा? क्या ब्राह्मण वोटों के जरिये चुनावी वैतरणी पार लगाने की कवायद हो रही है? यह नजरिया तो पार्टी की कथित रीति-नीतियों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। क्या इसे अब यूं समझें कि सत्ता की राजनीति में सब कुछ जायज है?

कहां तो कबीर सदियों पहले कह गये थे कि 'जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिये ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान।' कहां इक्कीसवीं सदी में जाति उजागर करके चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत लगाई जा रही है? वह भी उस आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पार्टी विद डिफरेंस का दावा करती है। जिसने सड़ी-गली राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के सपने भारतीय जनमानस को दिखाकर नई उम्मीदें जगाई थीं। झाड़ू लेकर पार्टी राजनीतिक शुचिता के लिए सफाई करने चली थी। ऐसा ?भी नहीं है कि पार्टी की कथनी-करनी का अंतर पहली बार उजागर हुआ हो। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह दूसरी पार्टी से आये धनाढ्य लोगों को पार्टी ने राज्यसभा का दरवाजा दिखाया, तब भी पार्टी की नेक-नीयत पर सवाल उठे थे। सवाल उठे थे कि क्या केजरीवाल को जाति-बिरादरों के अलावा अन्य योग्य लोग नहीं मिले? क्यों चुनाव में धन्ना सेठों को ?उतारने की जरूरत पड़ी? क्यों पार्टी को कोई आम आदमी नहीं मिला जिसे राज्यसभा में बैठाया जा सकता था? जाहिर-सी बात है बदलाव की आंधी लाने का दावा करने वाली पार्टी सत्ता के लिए किये जाने वाले प्रपंचों के हमाम में बेनकाब हुई है। शुचिता की गंगा सत्ता के खेल में मैली नजर आई। हरियाणा के मौजूदा घटनाक्रम में उसी सोच की बानगी नजर आती है।

ट्रंप की सनक से त्रस्त वैश्विक व्यवस्था

अब तक जी-7 संगठन की वार्षिक बैठकों में भाईचारा देखने को मिलता रहा है। इसमें शामिल विकसित अर्थव्यवस्थाओं का दुनियाभर के सकल घरेलू उत्पाद में 46 फीसदी हिस्सा बनता है। वैश्विक व्यवस्था बनाने में इस संगठन का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस महीने के शुरू में वैंकूवर में हुई बैठक में अपने व्यवहार से सौहार्दपूर्ण वातावरण को?भंग किया। इस शिखर वार्ता पर व्यापारिक संबंधों पर सुलग रहे तनाव की परछाई छाई रही, जिसमें अमेरिका ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए जी-7 गुट के भागीदार सदस्य देशों से भी आयात होने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। ट्रंप ने उस शिखर वार्ता घोषणापत्र को तिलांजलि दे दी, जिस पर उन्होंने पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। और तो और कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रुडो को 'बेईमान और कमजोर' ठहरा दिया। इससे क्षुब्ध होकर हालांकि गुट के यूरोपियन सदस्यों ने एकजुट होकर ट्रंप के बयानों का कड़ा संज्ञान लिया। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो पहले ही चीन और उत्तरी कोरिया के मामले पर ट्रंप के पूर्ववर्ती यू-टर्नों से हिले हुए हैं, उन्होंने अलबत्ता चुप रहना मुनासिब समझा।

दरअसल, ट्रंप के अप्रत्याशित स्वभाव और बदतमीज रवैये से न केवल उनके सहयोगियों को बल्कि दुनिया के तमाम देशों को झटका लगा है। उनके इस व्यवहार ने वैश्विक व्यवस्था को एक नाटकीय प्रपंच में तब्दील करके रख दिया है। उन्होंने आते ही 'अंतर-प्रशांत भागीदारी' (ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप) में अमेरिकी सदस्यता छोड़ दी थी, जबकि इस मंच के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र की आर्थिकियों में सहयोग किया जाता रहा है। इसमें कनाडा-अमेरिका से लेकर जापान तक पड़ने वाले देशों के अलावा दक्षिण कोरिया और 'असियान' संगठन के सदस्य देश भी शामिल हैं। चीन अब अपने बृहद आर्थिक सहयोग नामक नए मंच को आगे बढ़ाने में लगा है, इसके लिए वह 'असियान' संगठन के देशों के अतिरिक्त इसके संवाद-भागीदार सदस्यों जैसे कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी साथ जोड़ना चाहता है। अमेरिका के नए निर्णयों से उसे आर्थिक दबदबा बढ़ाने में आसानी होगी। वैश्विक व्यवस्था को अस्थिर बनाने वाली ट्रंप की नीतियों में एक अन्य है 'उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संधि' को निरस्त करने का उनका दृढ़ इरादा। इससे पहले उन्होंने छह मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया था, ट्रंप ने ईरान पर भी एकतरफा निर्णय में परमाणु प्रतिबंध लगा दिए हैं। उन्होंने हैती और कुछ अफ्रीकी देशों को 'गोबर-देश' कहकर अपमानित किया है।

ट्रंप ने संपूर्ण येरुशलम शहर को बतौर इस्राइल की राजधानी मान्यता देकर वहां पहले से व्याप्त इस्राइली-फिलीस्तीनी तनाव में नया इजाफा और अनिश्चितता भर दी है, उन्होंने वैश्विक एकराय को नजरअंदाज किया है, जिसमें कहा गया है कि पूरबी येरुशलम फिलीस्तीनियों के अधिकार क्षेत्र में रहे। ट्रंप अपने प्रत्याशित स्वभाव के चलते अपने सहयोगी मुल्कों, दक्षिण कोरिया और जापान की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए वे सिंगापुर में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग से शिखर वार्ता की। ट्रंप और किम ने अपनी भेंट को 'बृहद, गहरे और संजीदा विचार-विमर्शों के आदान-प्रदान' वाली ठहराया है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने कई महीनों से लंबित दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त सैनिक अभ्यास को भी रद्द कर दिया अर्थात उन्होंने किम के भरोसे को माना कि उत्तर कोरिया अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम स्थगित कर देगा। ये तमाम काम अनाड़ीपन दर्शाते हैं और इससे दक्षिण कोरिया और जापान का अमेरिका पर भरोसा कमजोर पड़ गया है। यह संभावना कम ही है कि उत्तर कोरिया वादे के मुताबिक परमाणु हथियारों का भंडार नष्ट कर देगा। किसी को भी हैरानी हो सकती है कि जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इतना कुछ हो गुजरने के बावजूद महज एक मूकदर्शक बनना गवारा कर सकते हैं, वह भी तब जब उनके दो निकटवर्ती पड़ोसी यानी चीन और उत्तर कोरिया के पास घातक मिसाइलों और परमाणु अस्त्रों का भण्डार हो, तिस पर तुर्रा यह कि अब इस संबंध में अमेरिका की मूक सहमति स्पष्ट दिखाई दे रही है।

भारत भी ट्रंप की आर्थिक नीति 'अमेरिकी हित सर्वोपरि' की मार झेलने वालों में एक देश है। भारत से आयात किए जाने वाले स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिका ने जो अतिरिक्त शुल्क लगाया है उसको लेकर भारत ने यह मामला विश्व व्यापार संगठन में उठाने के अलावा प्रतिकर्म में अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। वर्ष 2017-18 में अमेरिका-भारत आयात-निर्यात में परस्पर अनुपात में फर्क 21 बिलियन डॉलर का है। स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन उस 'जीएसपी ट्रेड तरजीह' को खत्म करना चाहता है जो 1974 से भारत को प्रदान की गई थी। उसकी मांग है कि अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आयात पर भारत ने जो रोक लगा रखी है उसे खत्म किया जाए। जहां एक ओर ट्रंप चीन से होने वाले आयात पर लगभग 50 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने की तजवीज कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ के पुल बांधते हुए चीन को विशेष दर्जा देने की बात का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी संसद द्वारा चीन के अग्रणी एंड्रॉयड मोबाइल निर्माता जेडटीई पर लगाए गए प्रतिबंध को तुड़वाने हेतु ट्रंप ने निजी तौर पर हस्तक्षेप किया था। जबकि इस कंपनी ने यह कबूला था कि ईरान और उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपने उत्पाद भेजे थे।

निकट भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच बहुत-सी उच्च-स्तरीय बैठकें होने को हैं, इसलिए जब ट्रंप यह अपेक्षा रखेंगे कि उन नीतियों पर, जिन्हें वह अमेरिकी हित के लिए बहुत जरूरी बताएंगे, भारत का समर्थन मिले, तो हमें सोच-समझ कर ही अपनी सहमति देनी होगी। सुरक्षा उपकरणों या सिविलियन ट्रांसपोर्ट हवाई जहाजों जैसे किसी बड़े खरीद वाले सौदे को हमें अमेरिका के तयमुश्त राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी संकेतों के साथ जुड़वाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका के किन्हीं कृत्यों से भारत-रूस रक्षा संबंध कमतर न बनने पाएं। हमें विभिन्न मंचों जैसे कि भारत-रूस-चीन के बीच त्रिपक्षीय संवाद बैठकों के अलावा 'ब्रिक्स' और 'एससीओ' संगठनों में भी रूस और चीन के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अमेरिका भारत को हल्के में न ले सके। लगता है अमेरिकी रक्षा सचिव मैट्टिस और विदेश सचिव पोम्पियो को भारत की नीतियों, अधिमान और रुतबे की वास्तविक समझ है। भारत के लिए अच्छा यह है कि अमेरिकी संसद के दोनों सदन हमारे लिए द्विपक्षीय समझ रखते हैं। हमें अफगानिस्तान में अमेरिकी नीतियों पर नजदीक से नजर रखनी होगी।

हालांकि देश के पश्चिमी इलाके के नागरिकों ने ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मतदान दिया था परंतु आज वहां भी पहले की बनिस्बत लोग धार्मिक द्वेष और नस्लीय नफरत की तरफ अधिक लिप्त होने लगे हैं। इस तथ्य की तारीफ की जा रही है कि आर्थिक नीतियों जैसे कि कर में छूट की वजह से स्टॉक मार्किट में उछाल आने के साथ बेरोजगारी घटने लगी है। अमेरिका में खासकर छोटे शहरों के श्वेत अमेरिकी नागरिकों में ट्रंप की आव्रजन नीतियों की स्वीकार्यता और समर्थन साफ तौर पर दिखाई देता है। बड़ी संख्या में अमेरिकी लोगों को लगता है कि ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' वाला नारा जायज है। इसलिए 'ग्रीन कार्ड' लेने के इच्छुक और वे लोग जो अमेरिकी 'उदारवाद' को पहले की तरह जारी रखने की अवास्तविक आकांक्षा पाले बैठे हैं, उनको सलाह है कि उपरोक्त बातों को अपने जहन में रखें।

ऋणों से जूझती वैश्विक व्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा संकलित दस ऐसे राष्ट्रों की सूची में, जिनके जीडीपी के बनिस्बत उनके ऋणों का अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तीन यूरोपीय देश-ग्रीस, इटली तथा पुर्तगाल-शामिल हैं, जबकि इस सूची में शीर्ष पर जापान है, जिसने अपने जीडीपी के 240 प्रतिशत के लगभग ऋण ले रखे हैं. आम उम्मीद के विपरीत, ये बुरी तरह ऋणग्रस्त देश सबसे गरीब देशों में शुमार नहीं हैं, न ही वे कोई लापरवाह और शाहखर्च राष्ट्र माने जाते हैं. जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया जैसे मौद्रिक रूप से दकियानूसी देश भी इसमें खासे ऊपर हैं. मुद्दे की बात यह है कि विश्व में विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा ऋण लेते जाने की प्रवृत्ति आसमान छू रही है, जिसका पुनर्भुगतान किस तरह किया जा सकेगा, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है. जापान एवं भारत इस मायने में विवेकशील रहे हैं कि उनके अधिकतर ऋण बांड अपने ही देश की मुद्रा में जारी किये जाते हैं, जो उनके ही नागरिकों द्वारा लिये जाते हैं. अत: उनका अंतरराष्ट्रीय चूककर्ता बनने की संभावना बहुत कम है. कुछ लोग यह समझ सकते हैं कि सरकारों द्वारा किसी पुराने ऋण की वापसी के लिए उन्हें केवल नये ऋण बांड जारी करने की जरूरत है और यह प्रक्रिया अंतहीन रूप से चल सकती है. जापान जैसे समृद्ध देश की ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर ऐसी ही रणनीति का फल है. मगर सभी देशों को जापानी ऋण बांड की तरह ए+ की रेटिंग नहीं मिला करती. इसलिए, अपनी रेटिंग और विश्वसनीयता की रक्षा के लिए भारत जैसे देश मौद्रिक दायित्व को विधान द्वारा लागू कराते हैं. यह कुछ वैसा ही है, जैसे सरकार ने अपने हाथ कानून द्वारा बांध रखे हों, जो घाटे और ऋणों को कानूनी रूप से तयशुदा एक सीमा के आगे नहीं बढ़ा सकते. यह वही नजरिया है, जिसे यूरोपीय यूनियन के देशों ने 1992 की मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा स्वीकार तो किया, पर जिसका यूनियन के सबसे बड़े देशों ने चार वर्षों के भीतर ही उल्लंघन कर डाला. दरअसल, जब व्यावसायिक चक्र विपरीत हो उठता है अथवा जब मतदाता ज्यादा सरकारी व्ययों की मांग करने लगते हैं, तो कानूनी बाध्यकारी सीमाएं शिथिल किये बगैर सरकारों के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता. निजी क्षेत्र की ऋण समस्या भी उतनी ही गंभीर है. साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट मुख्यत: अत्यधिक ऋणग्रस्तता, शिथिल विनियम, लचीली रेटिंग एजेंसियों, लालची बैंकों तथा लापरवाह कर्जखोरों के घालमेल से पैदा हुआ था. भारत इस संकट से बच सका, क्योंकि यहां ऋणों के नियम कड़े करने, आवासन और वैसे ही अन्य ऋणों के जोखिम भार ऊंचे करने तथा विनियामक निगरानी जैसे कदम लागू थे. पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम ऐसे ही किसी अगले संकट से भी सुरक्षित हैं. सच तो यह है कि आज पूरा विश्व मौद्रिक तरलता में डूबा है और ऋणस्तर पहले कभी की बजाय कहीं ऊंचा है.

अमेरिका, यूरोपीय यूनियन तथा जापान के केंद्रीय बैंक पिछले लगभग एक दशक से मुद्रा छापने एवं ब्याज दरों को शून्य के करीब रखने की नीति पर चलते रहे, ताकि बैंक ऋण एवं साख वृद्धि अधिकाधिक हो सके. साख सृजन के द्वारा बैंक मुद्रा आपूर्ति सृजित करते हैं. इससे मुद्रास्फीति हो सकती है, पर कीन्स के सिद्धांत के अनुसार यह आर्थिक वृद्धि का जनक भी होता है. परंतु, यदि उपभोगकर्ताओं एवं निवेशकों में भविष्य के प्रति भरोसा न हो, तो मुद्रा छापते जाने के अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते. दुर्भाग्य से हम बैंकों के विफल होने और डूबते ऋणों की घटनाएं भी अभूतपूर्व ढंग से देख रहे हैं. बैंकों की विफलता का बोझ अंतत: उनके जमाकर्ताओं या करदाताओं पर ही पड़ता है. इसे कैसे रोका जा सकता है? इसका कोई आसान समाधान तो नहीं है. इसके लिए विनियामक निगरानी, कड़ाई से अमल, ऋणों के मजबूत शासी मानक, ऋणों के बदले पर्याप्त जमानत, दिवाला समाधान की कुशल प्रक्रिया तथा एक मजबूत साख संस्कृति आवश्यक है.

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

एनडीए में जदयू की भूमिका

साल 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में तेजी से राजनीतिक बदलाव हुए. 161 सीटों के साथ भाजपा संख्या बल के शिखर पर थी, लेकिन कोई बड़ा गठबंधन न होने के कारण महज 14 दिनों में ही यह सत्ता से बाहर हो गयी. स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने इस संख्या बल को लेकर लोकसभा में अपना दर्द बयां किया था कि 'कांग्रेस पार्टी पराजित हुई और मुझे बड़े दल के रूप में जनता का विश्वास मिला, लेकिन मैं इस संख्या बल के सामने नतमस्तक होता हूं और इस्तीफा देता हूं.' इसके बाद जनता दल के नेता एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जिन्हें कई क्षेत्रीय दलों का सहयोग प्राप्त हुआ और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी.

लेकिन देवगौड़ा ने सीताराम केसरी के इशारे पर नृत्य करने से मना कर दिया. उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और इंदिरा गांधी के सहयोगी इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया. इस गठबंधन की मियाद भी लंबी नहीं रही. राजीव गांधी की हत्या में द्रमुक की भूमिका को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं की मांग रही कि सरकार में शामिल द्रमुक के मंत्रियों को बाहर किया जाये. इसका पटाक्षेप गुजराल के इस्तीफे से हुआ. यद्यपि यूपीए-2 से लेकर आज तक द्रमुक कांग्रेस के साथ ही है. कांग्रेस के निर्देशन में कमोबेस यही हाल चंद्रशेखर के साथ भी हुआ. हरियाणा पुलिस के दो सिपाहियों के गुप्तचरी के आरोप में एक सरकार स्वाहा हो गयी.

वस्तुत: गठबंधन की राजनीति के दो नायक हुए. पहला ज्योति बसु और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी. बसु के 25 वर्षों के शासन में सहयोगी पार्टी की सीट व विभाग जस के तस बने रहे. यह गठबंधन के स्वर्णिम क्रियान्वयन का बड़ा उदाहरण है. 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद भाजपा अलग-थलग पड़ गयी. यद्यपि लोकसभा व विधानसभाओं में इसकी संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन सहयोगी दल के रूप में सिर्फ शिवसेना का ही समर्थन मिला. उधर बिहार में लालू प्रसाद के कुशासन, जातिवादी तथा अहंकारी नेतृत्व के कारण जनता दल में बड़ा विद्रोह हुआ.

जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रबी राय, चंद्रजीत यादव, सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल गफूर सरीखे नेता विद्रोह के बाद 1994 में समता पार्टी का निर्माण करा चुके थे. ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी, जनता दल से अलग होकर बीजेडी, टीडीपी सरीखी पार्टियां अपनी सार्थक कारगर भूमिका की तलाश में थीं. भाजपा का बंबई में राष्ट्रीय अधिवेशन था. इसी दौरान जॉर्ज फर्नांडिस जसलोक अस्पताल में भर्ती थे. लालकृष्ण आडवाणी उनसे कुशल-क्षेम पूछने गये हुए थे, जहां नीतीश कुमार भी मौजूद थे. आडवाणी भाजपा अधिवेशन में समता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति चाहते थे और ऐसे लचीले गठबंधन की इच्छा भी रखते थे, जिसमें गैर-कांग्रेसी दलों को भी शामिल किया जा सके.

अधिवेशन में नीतीश की उपस्थिति व संबोधन राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव का मील का पत्थर साबित हुआ. हालांकि, 1996 के लोकसभा व विधानसभा के चुनावों में समता पार्टी पराजित हुई, लेकिन देश की राजनीति के लिए गठबंधन की राहें आसान हो गयीं. मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के लागू होने के बाद बिहार में लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव बड़े नेता के रूप में उभरे. मुलायम सिंह अनुभवी व समाजवादी आंदोलन की मुख्यधारा की उपज थे जबकि लालू केवल छात्र राजनीति की उत्पत्ति थे. बिहार में कुशासन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक जनजागरण शुरू हुआ. जॉर्ज और नीतीश कुमार की बड़ी-बड़ी सभाएं होने लगीं, जिसमें पिछड़े तबकों के विभिन्न वर्गों तथा खासकर अतिपिछड़ों को संगठित करने का काम किया गया.

नि:संदेह कुशवाहा जाति के बड़े नेता के रूप में सकुनी चौधरी भी नीतीश के इस मुहिम का हिस्सा बने, जिसे लोग 'लव-कुश' की राजनीति भी कहते थे. यह दौर लालू के खिलाफ पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का था. 1998 तथा 1999 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन के नतीजे दिखने शुरू हो गये थे तथा अटल बिहारी की अध्यक्षता व जॉर्ज साहब के संयोजन में एनडीए की स्थापना हुई. विवादास्पद मुद्दों से एनडीए ने दूरी बनायी, जिसमें तय था कि अनुच्छेद-370 यथावत रहेगा, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन व दोनों धर्म गुरुओं के संयुक्त संतुति के अनुसार रहेगा तथा सामान नागरिक संहिता में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा.

इस तरह से वाजपेयी के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों की लंबी कतार लग गयी, जो इस गठबंधन में शामिल हुए. टीएमसी, टीडीपी, अकाली दल, समता पार्टी, कुछ समय के लिए बसपा समेत कई दल इसके अंग बने. किसी भी वैचारिक या आर्थिक मुद्दे पर 2005 तक कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ.

जहां तक एनडीए में जदयू की भूमिका का प्रश्न है, जदयू सामाजिक न्याय की राह चल सबके विकास को संकल्पित रहा है. यह भ्रष्टाचार के सवालों पर बनी-बनायी सरकार तक का त्याग करने का साहस रखती है. पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जेपी और वीपी सिंह के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा रह चुके हैं. आपातकाल में जेल जा चुके हैं. यही कारण रहा कि लालू और उनके परिवार द्वारा संपत्ति अर्जित करने के मामले के सार्वजनिक होने के बाद गठबंधन चलाना असंभव हो गया था. नीतीश सुशासन के पैरोकार रहे हैं, इसलिए सिर्फ सत्ता में बने रहने मात्र

अपना आकाश तलाशने की जद्दोजहद

खुद से सीखने की प्रक्रिया थोड़ी लम्बी और जटिल होती है। मगर होती बहुत कारगर है। धीरे-धीरे सीखने वालों की प्रतिक्रियाओं का मतलब, महत्व और संघर्ष के आयाम दूसरों को भी बखूबी समझ आने लगते हैं। पिछले दिनों जनवादी महिला समिति द्वारा कैथल, भिवानी, हिसार, रोहतक में किए गए ग्रामीण महिलाओं के सम्मेलन में ये बातें बखूबी उभर कर आईं। सौभाग्य से इन सम्मेलनों में आज़ाद हिन्द फ़ौज की एकमात्र कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिणी अली सहगल भी साथ थीं। इन सम्मेलनों में अनेक गांव से आई महिलाओं द्वारा रखे गए विचारों का सार था ='जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कोई सुनाई नहीं करता।'

तथाकथित विकास की दौड़ में पीछे छूट गई कम पढ़ी-लिखी परन्तु ठाढ़ी कमेरी इन महिलाओं को उनके साथ चल रहे सलूक ने एक तो यह जता दिया है कि थोड़ी अच्छी भाषा बोलने वाली, साफ़-सुथरे कपड़े पहनने वाली महिलाएं उनसे श्रेष्ठ होती हैं। क्योंकि तमाम समझाने के बावजूद उम्र में ज़्यादा ये महिलाएं हमें आदतन 'जी' कहकर ही संबोधित कर रही थीं। हरियाणा में ग्रामीण महिलाओं को उनकी विकास की ज़रूरतों के ईर्दगिर्द संगठित करने के प्रयास छिटपुट व बिखरे-बिखरे से हुए हैं। हरियाणा के पंचायत मंत्री तथाकथित पढ़ी-लिखी पंचायतों को कितने ही स्टार बांटते फिरें परन्तु इन महिलाओं से किसी पंचायती का दूर-दूर तक का संवाद नज़र नहीं आया। इस तरह से देखें तो जो महिलाएं बोल रही थीं, उन्होंने स्वयं खेतीबाड़ी, मेहनत-मजदूरी, गोबर-पानी, सेवा-पानी व पालन-पोषण करते हुए, जो देखा वही बयां किया। गरीब तबके की महिलाएं मनरेगा में काम करती हैं और वे भी तब जब किसी ओर तरह से रोज़ी-रोटी चलाने का क़तई विकल्प न हो, क्योंकि सबसे हाड़ तोड़ काम इस योजना में कराया जाता है। मगर फिर भी इनकी मज़दूरी दो-दो साल की लटकी पड़ी है। पिछले क़रीब दस-बारह साल से नये राशन कार्ड नहीं बने, महंगाई इतनी ज़्यादा है तो परिवारों का पेट कैसे पालें। इस जानलेवा गर्मी में बिजली दो घण्टे आती है, उसका भी समय निश्चित नहीं, बच्चे रातभर सोने नहीं देते, पूरा दिन कैसे शरीर चले? पीने के पानी को लेकर हालत ऐसी कि जब गर्मी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े तब पहले जितना भी न मिले। ऐसी स्थिति का लाभ प्राइवेट पानी ठेकेदार उठाते हैं। इन सब पर भी पेट पर पट्टी बांधते हुए वे गाड़ी खींचने को तैयार हैं, परन्तु सबसे बड़ी समस्या है दारू पीने की। हाड़ तोड़ कर जो कुछ भी वे जुगाड़ने की कोशिश करती हैं, उसकी आदमी दारू पी जाते हैं, विरोध करें तो मारपीट। अब तो बच्चे व किशोर भी दुकानों से पाऊच लेकर नशा करते हैं। पंचायतों से गांव में दारू का ठेका न खोलने का प्रस्ताव अगर किसी तरह कहीं पास कराया तो सरकार ने मामूली मीन-मेख कर रिजेक्ट कर दिया। आज के दिन गांव में अगर कोई रौनक़ बची हुई है तो वह है दारू के ठेकों पर। बुज़ुर्गों, बच्चों की बीमारी, पशुओं की बीमारी स्वास्थ्य विभाग का बैठता ढर्रा। इन तमाम सहयोगी ढांचों के अभाव व उनसे जुड़ी पीड़ाएं ग्रामीण महिलाओं की दुखद तस्वीर को उकेर कर रख देती हैं।

सुबह सबसे पहले उठकर काम लगना व रात को सबसे बाद में खाट पकड़ना। शायद इसी वजह से 70 प्रतिशत महिलाओं व उनके गर्भ से पैदा होने वाले बच्चों में खून की कमी पाई जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए चलाई गई आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मदर ग्रुप, मिड-डे मील आदि योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की तरह वेतन की बजाय मानदेय देकर स्वयं सरकार उनका शोषण कर रही है।

पश्चिम रेलवे-भावनगर मण्डल

ड्राइवर के रनिंग रुम की मरम्मत तथा प्रथम तल को उजाड़ना

सं. **DRM/EL/ET/BVP/2018-19/13** दिनाँक **27/06/2018**. मण्डल रेलवे प्रबंधक (बिजली) पश्चिम रेलवे, भावनगर परा, भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्न कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते हैं **निविदा संख्या: 07/2018-19 कार्य का नाम** : बोटाद-ड्राइवर के रनिंग रुम की मरम्मत तथा प्रथम तल को उजाड़ना । **कॉन्ट्राक्ट वैल्यु:** ₹ 11,05,797/- **टेन्डर फी** : 2,000/- **ईएमडी रकम** : ₹ 22,120/- **पता:** मण्डल रेलवे प्रबन्धक, (बिजली), पश्चिम रेलवे, भावनगर परा-364003 । निविदाकर्ता केवल ऑनलाईन लिंक **www.ireps.gov.in** द्वारा आवेदन करें कृपया वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर सम्पर्क करें । अन्तिम दिनाँक ऑनलाईन आवेदन की **दिनाँक 06/08/2018 को 15.00 बजे** । 40

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly